

1. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 18 जून को प्रस्तावित वाराणसी दौरे को लेकर तैयारियां तेज : प्रधानमंत्री किसान सम्मेलन में किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त करेंगे जारी।
2. शहरी क्षेत्रों में तीन दिन और ग्रामीण क्षेत्रों में पन्द्रह दिन में मिलेगा नया बिजली कनेक्शन : पावर कार्पोरेशन ने लागू किया नया आदेश।
3. केंद्र ने सर्वोच्च न्यायालय को बताया कि नीट परीक्षा में एक हजार 563 छात्रों को ग्रेस अंक देने का फैसला किया गया रद्द : सरकार ने कहा—प्रश्न पत्र लीक होने का नहीं मिला कोई सबूत।

और

4. मौसम विभाग ने प्रदेश में अगले तीन दिनों के लिये जारी किया लू का रेड अलर्ट : 25 से 35 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती हैं हवाएं।

---

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तीसरी बार शपथ ग्रहण के बाद अपनी संसदीय क्षेत्र वाराणसी में आगामी 18 जून को दौरा प्रस्तावित है। प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी है। वहीं भाजपा के कार्यकर्ता प्रधानमंत्री के भव्य स्वागत के लिये तैयार है।

प्रधानमंत्री प्रस्तावित दौरे के दौरान काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे और गंगा आरती में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री के दौरे के बारे में भारतीय जनता पार्टी के काशी क्षेत्र के अध्यक्ष दिलीप पटेल ने बताया कि प्रधानमंत्री 18 जून को वाराणसी में किसान सम्मेलन को संबोधित करेंगे और किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त भी जारी करेंगे।  
बाइट.....

*काशी के आम जनमानस इस बात से गौरवान्वित है कि हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी हमारे सांसद का आगमन 18 जून को हो रहा है और हम सभी लोगों को माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत अभिनंदन करने का अवसर मिलेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी सर्वप्रथम सेवापुरी विधानसभाक्षेत्र के मेहंदी सभा में पहुंचेंगे, वहां पर एक विशाल किसान संवाद जनसभा का आयोजन है, उसी स्थल पर माननीय प्रधानमंत्री जी किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त जो 20,000 करोड़ रुपये की राशि है उसको जारी करेंगे।*

---

उत्तर प्रदेश पावर कार्पोरेशन ने विद्युत उपभोक्ता अधिकार नियम दो हजार बीस के अन्तर्गत बिजली कनेक्शन देने के संबंध में नया आदेश लागू किया है। इस आदेश के जरिए बिजली कनेक्शन के लिए समय सीमा तय कर दी गयी है। नये नियम के अन्तर्गत नगर निगम वाले शहरी क्षेत्रों में उपभोक्ताओं को तीन दिन में बिजली कनेक्शन उपलब्ध होगा, जबकि नगर पालिका वाले शहरों में सात दिन और ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकतम पंद्रह दिन में बिजली कनेक्शन देना अनिवार्य होगा। कनेक्शन के लिए आवेदन

करने की तारीख से तय समय सीमा में कनक्शन न देने पर संबंधित विद्युत वितरण निगम को आवेदनकर्ता को प्रतिदिन पचास रूपये की दर से मुआवजा देना पड़ेगा।

---

उत्तर प्रदेश पुलिस में आउटसोर्सिंग से भर्ती का आधिकारिक पत्र वायरल होने के बाद यूपी पुलिस ने स्पष्टीकरण जारी किया है। यूपी पुलिस ने बयान जारी कर स्पष्ट किया है कि यह लेटर त्रुटिवश जारी हो गया था, जिसे निरस्त कर दिया गया है। विभाग की ओर से सोशल मीडिया पोस्ट में कहा गया कि पुलिस विभाग में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की आउटसोर्सिंग की व्यवस्था पहले से प्रचलित है। त्रुटिवश चतुर्थ कर्मचारियों के स्थान पर मिनिस्टीरियल स्टाफ के लिए जारी पत्र को निरस्त कर दिया गया है। इस प्रकार का कोई भी प्रकरण पुलिस विभाग एवं शासन स्तर पर विचाराधीन नहीं है।

---

केंद्र ने सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया है कि एक हजार पांच सौ 63 नीट छात्रों को एमबीबीएस, बीडीएस तथा अन्य पाठ्यक्रमों में दाखिला लेने के लिए अतिरिक्त अंक देने का फैसला रद्द कर दिया है। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और संदीप मेहता की पीठ को केंद्र तथा राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने बताया कि जिन विद्यार्थियों को अतिरिक्त

अंक मिले थे, उनके पास 23 जून को दोबारा परीक्षा देने का विकल्प रहेगा। एजेन्सी ने कहा कि पहले से घोषित काउंसलिंग कार्यक्रम में कोई बदलाव नहीं होगा क्योंकि दोबारा होने वाली परीक्षा के परिणाम 30 जून तक घोषित किए जाएंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने आज इस बात को दोहराया कि वह नीट-यूजी 2024 प्रवेश काउंसलिंग प्रक्रिया पर रोक नहीं लगाएगा।

उधर, सरकार ने कहा है कि राष्ट्रीय पात्रता-प्रवेश परीक्षा में प्रश्नपत्र लीक होने का कोई सबूत नहीं मिला है। नई दिल्ली में शिक्षा मंत्रालय का कार्यभार संभालने के बाद मीडिया से बातचीत में केन्द्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने छात्रों और अभिभावकों को आश्वासन दिया कि केंद्र उन्हें न्याय दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि मामला सर्वोच्च न्यायालय में है और परीक्षा के संबंध में शिक्षाविदों की एक समिति भी बनाई गई है। बाइट.....

*आपको स्पष्ट करूं दियर इज नो करप्शन, पेसिफिक घटनाएं जो आए हैं उसको सरकार गंभीरता से लिया है। जो घटना हमारे सामने आई निश्चित रूप में दोषियों को उसमें दंड दिया जाएगा। लेकिन मैं विद्यार्थियों को मुख्य तौर पर अभिभावकों को आश्वस्त करना चाहूंगा, भारत सरकार और उसकी इन्स्ट्रूमेंट एनटीए कमिटेड है बच्चों को ट्रांसपेरेंट तरीका से न्याय देने के लिए। पेपर लीक की घटना के कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है।*

---

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, सीबीएसई ने दसवीं और बारहवीं की शैक्षणिक सत्र दो हजार तेइस-चौबीस के लिये

कम्पार्टमेंट परीक्षा की तिथियां जारी कर दी हैं। इसके अन्तर्गत दसवीं की परीक्षाएं पन्द्रह से बाइस जुलाई तक और बारहवीं की परीक्षाएं पन्द्रह जुलाई को आयोजित की जायेगी।

---

### ब्रेक

यह समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिये आप हमारी वेबसाइट न्यूज़ ऑन ए0आई0आर0 डॉट जी0ओ0वी0 डॉट आई0एन0 पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज़ ऑन एआईआर लखनऊ पर भी सुन सकते हैं।

प्रादेशिक समाचारों के इस बुलेटिन में आपका फिर से स्वागत है।

---

अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को सफलतापूर्वक संपन्न करने के लिए वाराणसी के संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में शपथ ग्रहण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर विश्वविद्यालय की कुलपति बिहारी लाल शर्मा ने उपस्थित कर्मियों को योग को अपने दैनिक जीवन में जोड़ने की शपथ दिलाई।

---

देश में नये आपराधिक कानून एक जुलाई से लागू हो जायेंगे। इसके तहत संगठित अपराध पर नकेल कसना संभव होगा। नये कानून में संगठित अपराध से निपटने के लिये एक समर्पित धारा का प्रावधान है। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 111 संगठित अपराध को परिभाषित करती है, जिसमें अपहरण, डकैती, साइबर अपराध और कई अन्य अपराधों को लक्षित किया जाता है। जो अपराध या तो स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं थे या पिछले कानून में मौजूद नहीं थे, उन्हें एक अलग धारा 112 छोटे संगठित अपराध के रूप में रखा गया है, जो स्पष्ट रूप से इसे स्नैचिंग, शॉपलिफ्टिंग, सट्टेबाजी या जुआ और परीक्षा पत्र बेचने जैसे अपराधों में परिभाषित करता है। व्यक्तिगत रूप से या संगठित अपराध सिंडिकेट द्वारा हिंसा, धमकी या जबरदस्ती का उपयोग करके की गई गतिविधियां अब दंडनीय हैं।

आर्थिक अपराधों में अब आपराधिक विश्वासघात, जालसाजी, हवाला लेनदेन, सामूहिक विपणन धोखाधड़ी और व्यक्तियों या बैंकिंग, वित्तीय संस्थानों को धोखा देने की योजनाएं जैसे अपराध भी शामिल किये गये हैं।

अगर अपराध के कारण जीवन की हानि होती है, तो अपराधी को या तो मृत्युदंड या आजीवन कारावास का सामना करना पड़ेगा। साथ ही कम से कम 10 लाख रुपये का अनिवार्य जुर्माना भी लगाया जायेगा। इसके अतिरिक्त,

संगठित अपराधों में सहायता करने वाले व्यक्तियों के लिये उचित दंड के प्रावधान मौजूद है।

इसके अलावा घोषित अपराधियों को उनकी सम्पत्ति जब्त करके दंडित किया जायेगा। साथ ही भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 अदालत को घोषित अपराधियों की अनुपस्थिति में मुकदमा चलाने की अनुमति देती है।

---

गाजियाबाद के हाजीपुर में बुधवार रात एक मकान में आग लगने से पांच लोगों की मौत हो गई। वहीं एक महिला और एक बच्चे को घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस घटना पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शोक जताया है और जिला प्रशासन को ज़रूरी कदम उठाने के निर्देश दिए हैं।

---

लखनऊ के अकबर नगर में चल रहा एलडीए का ध्वस्तीकरण अभियान अपने चौथे चरण में है। इस अभियान में अब तक 300 से ज्यादा अवैध मकान और कमर्शियल कॉम्प्लेक्स को ध्वस्त किया जा चुका है। इस बारे में डीसीपी सेंट्रल रवीना त्यागी ने बताया कि स्थानीय लोग अपने घर खाली कर सहयोग कर रहे हैं। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। 700 पुलिसकर्मी, पीएसी, एसडीआरएफ

की एक यूनिट और दमकल की गाड़ियां तैनात की गई हैं।  
ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों से निगरानी भी की जा रही है।

---

प्रदेश में भीषण गर्मी और लू का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग ने प्रदेश में अगले तीन दिनों के लिये लू का रेड अलर्ट जारी किया है। इस दौरान 25 से 35 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। बीते 24 घंटों में कई जनपदों में अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के ऊपर दर्ज किया गया। सबसे अधिक 47 दशमलव 5 डिग्री सेल्सियस तापमान कानपुर में रिकॉर्ड किया गया। इसके अलावा प्रयागराज में 47 डिग्री सेल्सियस, वाराणसी और हमीरपुर में 46 दशमलव दो डिग्री सेल्सियस, आगरा में 46 डिग्री सेल्सियस और झांसी में 45 दशमलव 7 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। भीषण लू के चलते रात के समय में भी तापमान में ज्यादा गिरावट नहीं हो रही है। बीते 24 घंटों में कई जनपदों में न्यूनतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किया गया है।

---

राज्य अध्यापक पुरस्कार के लिये परिषदीय स्कूलों के शिक्षकों की ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पन्द्रह जून से शुरू होगी। अध्यापक प्रेरणा वेब पोर्टल की मदद से दस



जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। राज्य अध्यापक पुरस्कार के लिये बनायी गयी प्रत्येक जिले की जिला चयन समिति दो-दो श्रेष्ठ शिक्षकों का चयन करेगी, फिर राज्य स्तरीय चयन समिति इसमें से एक-एक सर्वश्रेष्ठ शिक्षक को पुरस्कार के लिये चयनित करेगी।

(समाप्त)